ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 84-86**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

गरीबी : HCES के सर्वेक्षण रिपोर्ट के सन्दर्भ में विश्लेषण

डॉ0 रीता जायसवाल
सहायक आचार्य– समाजशास्त्र, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ0प्र0) भारत

Received-14.01.2025, Revised-20.01.2025, Accepted-26.01.2025 **E-mail:jayarg22@gmail.com**

सारांशः G20–2023 का मुख्य नारा 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' तय किया गया था, जिसकी बैठक भारत में आयोजित की गयी थी। वस्तुतः आज भी भारत विकसित देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ है, जिसकी मुख्य वजह गरीबी है। गरीबी को सामन्यतः आर्थिक संसाधनों की कमी के रूप में देखा जाता है, जिसके परिणाम नकारात्मक होते है। (सेन 1999, टाउनसेंड 1985)। आर्थिक विकास के विस्तार से गरीबी का दायरा सिकुड़ता दिखाई पड़े यह लक्ष्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास में तेज गति से वृद्धि दर्ज कर रही है तथा भारत 2030 तक सात ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की आर्थिकी बनकर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है।

कुंजीभूत शब्द– गरीबी, आर्थिक संसाधन, आर्थिक विकास, गरीबी का दायरा, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्तर, आर्थिक विकास

वृहद आर्थिक स्थायित्व, युवा आबादी, गतिशील व जीवंत लोकतंत्र और तटस्थ भू–राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण आर्थिक विकास को एक दिशा मिली है वही भूमि श्रम और कृषि के क्षेत्र में अति गम्भीरता से सुधार करने की आवश्यकता दिखाई देती है। उद्यमी अपनी पूंजी का निवेश अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए प्रयास करते है, साथ न्यूनतम जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते है। ऐसी परिस्थिति में भूमि, श्रम और कृषि जैसे संसाधनों का अनुपयुक्त दोहन की संभावना बढ़ जाती है, जिससे गरीबी का जन्म होता है। (World Bank, 2023) भारत जैसे कृषि प्रधान देश में 90.91 करोड़ जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जिनका भूमि, श्रम और कृषि पर स्वामित्व है। भारत में आर्थिक स्तर में विकास ने गरीबी जैसे सम्प्रत्यय के दायरे को सिकुड़ने के बजाय चौड़ा कर दिया है। जिसने वृहद स्तर पर समाज में आर्थिक असमानता को जन्म दिया है, जिसमें एक वर्ग सुविधा सम्पन्न बनाया तो दूसरी ओर एक वर्ग को समस्त सुविधाओं से वंचित कर रहा है। जिसको ध्रुवीकरण के रूप में देखा जा सकता है।

गरीबी को जीवन स्तर के निम्न स्तर की स्थिति के रूप में देखा जा सकता है जिसमें वंचिता का एक ऐसा स्तर जो वांछित जीवन स्तर से काफी अलग है। लोगों को गरीबी में जीवन यापन करना उस दशा को कहते है जब उनकी आय और संसाधन इतने अपर्याप्त होते है कि वे उस समाज में स्वीकार्य माने जाने वाले जीवन स्तर को पाने में वंचित रह जाते है, जिसमें वे रहते है। गरीबी में जीवन यापन करने की स्थिति में लोगों को कम आय, खराब आवास, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और आजीवन सीखने में बाधाओं आदि के माध्यम से कई नुकसान का सामना करते है। वस्तुतः गरीबी की वास्तविकता इसकी निरपेक्षता और सापेक्षता के परिणाम के रूप में प्रकट होती है। निरपेक्ष या दीर्घकालिक गरीबी का संबंध बुनयादि आवश्यकता से संबंधित मुद्दे (भूख से मरने, स्वच्छ पानी, आश्रय, कपड़े और स्वास्थ्य देखभाल) हैं। सापेक्ष, गरीबी का संबंध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में समग्र गरीबी की स्थिति को व्यक्त करती है जिसका संबंध गरीबी रेखा (न्यूनतम जीवनस्तर) पर जीवन यापन करना, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से दूर रखा जाता है और मौलिक अधिकारों तक उनकी पहुँच प्रतिबंधित होती है जिससे गरीबी सामाजिक निराशा का दर्पण बन जाता है।

विकासशील देश में गरीबी की निरपेक्ष व सापेक्ष लोच बहुत अधिक विषम दशा में है। इसका मुख्य कारण वितरण संबंधी असमानता को माना जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश जहाँ कुल आबादी का एक चौथाई से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कुल आबादी का 25.7 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे है तथा शहरी क्षेत्र में 13.7 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है। भारत में गरीबी का आधार आय की भिन्नता न अतिरिक्त आय के स्थान पर 'उपभोग व्यय' पर आधारित बनाया गया है।

विश्व बैंक ने भी गरीबी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि गरीबी का अर्थ खुशहाली से वंचित होना है जिसमें कम आय के साथ बुनियादि सामान व सेवाओं की पहुँच की असमर्थतता शामिल है।

भारत जैसे विकासशील देश में भी उपभोक्ता का आधार बनाकर घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (House hold Consumption Expenditure Survey, HCES) ने गरीबी के मापन हेतु भारत के सन्दर्भ में HCES 2022.23 के सर्वेक्षण रिपोर्ट जो ऐंजल नियम (1857) के आधार पर प्रस्तुत किया है:

Table-1
Absolute and MPCE by Item group in 2022-23 All India

Food Item	Rural	Average (MPCE F)	Absolute difference Urban	%	Share in MPCE	Total
Cereals & Cereals substitutes	185	235	50	4.91	3.64	-127
Pulses & their product	76	90	14	2.01	1.39	-0.62
Sugar & Salt	35	39	4	0.93	0.6	-0.33
Milk & Milk product	314	466	152	8.33	7.22	-1.11
Vegetables	203	245	42	5.38	3.8	-1.58
Fruits	140	246	106	3.71	3	0.09
Egg, Fish & Meat	185	231	46	4.91	3.57	-1.34
Edible Oil	136	153	17	3.59	2.37	-1.22
Spices	113	138	24	2.98	2.13	-0.85
Beverages, refreshment & Processed food	363	687	324	9.62	10.64	1.02

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

Food	1750	2530	780	46.38	39.17	-1.36
Pan, tobacco & intoxicants	143	157	14	3.79	2.43	-1.36
Fuel & Light	251	404	153	6.66	6.26	-0.4
Education	125	374	249	3.3	5.78	2.48
Medical	269	382	113	7.13	5.91	-1.22
Conveyance	285	555	270	7.55	8.59	1.04
Consumer service excluding conveyance	192	382	190	5.08	5.92	0.84
Misc. good, entertainment	234	424	190	6.21	6.56	0.35
Rent	30	423	393	0.78	6.56	5.78
Tav & Leaves	5	16	11	0.13	0.24	0.11
Clothing bedding and footwear	230	350	120	6.1	5.41	-0.69
Durable	260	463	203	6.89	7.71	0.28
Non-food total	2023	3929	1906	53.62	60.83	7.2
All items	3773	6454	2686	100	100	-

Sources: HCES-2022-23 Survey Report

State Wise data food Item and AbN Food. (Rural and Urban Area)

	Food Item			Non Food Item	
State	Rural	Urban		Rural	Urban
Andhra Pradesh	2149.18	2616.66		4870.29	6781.76
Assam	1862.36	2865.92		3432.4	6135.5
Bihar	1812.18	2258.52		3384.11	4767.69
Chhattisgarh	1125.91	1761.19		2466.16	4483.11
Gujarat	1867.09	2780.28		3798.3	6620.72
Haryana	2235.84	3148.41		4858.69	7910.51
Jharkhand	1336.74	2054.73		2763.27	4930.99
Karnataka	1975.79	2796.93		4397.47	7665.87
Kerala	2316.41	2549.06		5923.62	7078.21
Madhya Pradesh	1406.57	1928.95		3112.63	4487.29
Maharashtra	1640.04	2484.64		4010.45	6657.03
Odisha	1420.68	2075.47		2949.62	5187.39
Punjab	2254.4	2590.72		5314.74	6543.51
Rajasthan	1863.81	2342.25		4263.14	5913.06
Tamilnadu	2239.26	2909.87		5310.33	7630.04
Telngana	2034.58	2889.94		4802.23	8158.44
Uttar Pradesh	1488.98	2045.93		3190.98	5040.41
West Bangal	1655.53	2345.68		3239.16	5267.2
India	1749.91	2529.67		3773.05	6458.69
%	**20.5**	**15.5**		**26.7**	**18.4**

Sources: HCES-2022-23 Survey Report

एचसीइएस (HCES-2022-23) के सर्वेक्षण रिपोर्ट के आकड़े गरीबी के परिदृश्य की एक अलग कहानी कहते है जो गरीबी के निरपेक्ष (Absoluteness) पक्ष के संभावित दशा–दिशा को प्रस्तुत करते है। एचसीइएस द्वारा प्राप्त आंकड़े के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत जैसे विकासशील देश में उपभोग के रूझान को लेकर व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लोग रोजमर्रा जीवन में खान–पान के अतिरिक्त पोषण स्वास्थ्य व सुख सुविधा की वस्तुओं पर भी खर्च को तरजीह दे रहे है। ग्रामीण परिवेश में 164 प्रतिशत और शहरी परिवेश में 146 प्रतिशत उपभोग की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी देखी गयी है। HCES 2022.23 के सर्वेक्षण रिपोर्ट के विश्लेषण करने पर यह तथ्य भी विशेष तौर पर उभर कर सामने आया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार ऐसा देखने को मिला कि घरेलू खर्च का 50 प्रतिशत से भी कम भोजन सामग्री पर किया गया है। जीवन स्तर में सुधार हेतु भोजन के अनुपात में व्यय अधिक किया गया है, जो गरीबी के मौद्रिक उपागम (Monetary approach) को दर्शाता है। सक्षमता उपागम (Capibilty approach) के मुख्य तथ्य हित (Well-being) की रूपरेखा को स्पष्ट रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है (अमर्त्यसेन, 1999) भारत जैसे विकासशील देश में पिछड़ेपन के मुख्य उपागम सामाजिक बहिवेशन (Social Exclusion) जिसमें प्रजाति, जाति, धर्म आदि आधार पर भेदभाव व्याप्त है। आंकड़े में इसका अभाव है। व्यवहारिक सिद्धान्त जो गरीबी की व्याख्या करता है आंकड़े इसकी व्याख्या करने में असमर्थ है। विकासशील देश में एक विशेष प्रकार 'संस्कृति गरीबी' संस्कृति विद्यमान होती है। (लेविस, 1969)

इस प्रकार गरीबी पीढ़ियों से पारित नकारात्मक और प्रतिकूल सांस्कृतिक मूल्यों का परिणाम है।

गरीबी एक बहुआयामी संप्रत्यय है। किसी भी देश को गरीबी देश की श्रेणी में रखने के अनेक आयाम जिम्मेदार होते है। मात्र उपभोग के स्तर की जांच करने से हम लोगों के जीवन स्तर की श्रेणियाँ नहीं तैयार कर सकते है। फलतः गरीबी शब्द

सांस्कृतिक मान्यताओं, व्यक्तिगत कमी, भौगोलिक असमानता, आर्थिक, राजनीतिक संप्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ है। राजनीतिक सिद्धान्त की भूमिका को रेखांकित करने हेतु एजाज अहमद वानी द्वारा लिखित पुस्तक 'The spatia Tempral Dyanamic of Capitalist understands in India' जो कॉर्पोरेट पूँजीवाद के बाद की दुनिया में सुपर रिच के बढ़ते प्रभाव ने धरती को सोखते के रूप में देखा है। थॉमस पिकेटी ने ऐसे वातावरण में एक गम्भीर प्रश्न की ओर संकेत किया है कि बढ़ते हुए सुपररिच का गरीबों के प्रति उत्तरदायित्व क्या है? इस प्रश्न से निश्चित तौर पर वैश्विक न्याय का मोह भंग हो जाता है। नीरा चढोक नगरीय सिद्धान्त थॉमस पिकेटी के मौलिक रचना पर एक उत्तेजक प्रश्न किया कि भारत के निवासी का गरीबी के प्रति कोई कर्त्तव्य है? चढोक ने विकासशील देशों में दो प्रकार के एजेन्सी ने प्रश्नों को उजागर किया: गरीबो की एन्जेसी, अमीरो के एन्जेसी। अमीरों की एंजेसी में अभिनेता के रूप में धनिक लोग उस आर्थिक संरचना का एक हिस्सा है जो अधिकांश लोगों को विशेष रूप से गरीबो के भाग्य का आकार देते है। वैश्विक न्याय के एक डिपैरेचियल ढाँचे में धन शक्ति और संसाधनों के वैश्विक वितरण में एंजेटो का स्थान वैश्विक न्याय के कर्त्तव्यों के निर्धारण का अभिन्न अंग है। ये वर्ग जो पूँजीवादी लोकतंत्र में धन के बढ़ते संकेन्द्रण और निचले हिस्से तक आर्थिक विकास में लाभों को पहुँचाने की रणनीति का अभाव है। धन में संकेन्द्रकरण राजनीतिक शक्ति के वितरण और प्रभावशीलता पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। जिससे सुपररिच के पक्ष में नियमों की व्यवस्था निर्मित होती है, जिससे गरीब सामाजिक न्याय से वंचित पाए जाते है। संस्थागत राजनीति की प्रक्रिया अरबपति को जन्म दे रही है, जिसे गरीब के लिए संस्था की सही व्यवस्था के रूप नहीं देखा जा सकता है। गरीबी उन्मूलन असमानताओं की कमी, शांति, न्याय और समावेशी प्रत्ययों को संस्थानों के बीच एक जटिल संबंध को दर्शाता है।

सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनूस के श्जीतमम-मतव जैमवतलश पर विचार किया था, जिससे शून्य गरीबी, शून्य बेरोजगारी, शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शामिल है। गरीबी जो सतत विकास का प्रथम लक्ष्य है। इसको 'शून्य' करने की दिशा में मात्र संरचनात्मक सिद्धान्त पर बल न देकर व्यवहारिक व राजनीतिक सिद्धान्त को भी एकीकृत कर प्राप्त किया जा सकता है। मेयर और अन्य (2015) ने भी उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण में कम सहयोग के कारण सटीकता में गिरावट को खतरे के रूप में चिन्हित करते है। परिणाम यह कहा जा सकता है कि HECS के सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ें के आधार पर आय असमानता व उपभोग स्तर के आधार पर गरीबी जैसे गम्भीर संप्रत्यय का विश्लेषण अधूरा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. MOSPI (2024) Survey on Household consumption Expendifure-2022-23, National Sample survey office (NSSC). Ministry of Statistics and programme Implementation Government of India Report no 591. (HCES-2022-23)
2. Levvis, O (1969), Culture of Poverty, in D.T. Moynitian On Understanding Poverty Perspective of Social Science, New York, Basic Book.
3. Royce. E (2015), Poverty and Power, The problem of structural inequality, 2nd Ed. Lanham Rowman and Littlefield, ISBN. 978-14422-3804-4
4. Meyer, B.D. WK. Mokand. T.K. Sullivan (2015), Household survey in crisis, Journal of Economic Perspective, Vol-29, No-4, PP. 199-226.
5. Sen. A. (1999), Development as freedom, New York, Anchor Book.
6. Townsent. P (1985), A Sociological Approach to the Measurement of Poverty- A Rejoindeo to Professor Amartya Sen, Oxford Economic Paper Vol-37, No-4, PP. 659-668.
7. http://www.macrotrends,net/globalmetrics/countries/ind/india/ruralpopulation

*****